अमृत वाणी

काहिली जीवित मानव की मादकता है।

जैरेमी टेलर

कितने बेपरवाह हो सकते हैं लोग

हैरत होती है यह देखकर कि लोग बार बार जुर्माना चुकाने को तो तैयार हैं मगर यातायात नियमों का पालन करना नही चाहते। ऐसी बात नही कि ऐसे लोगों को यातायात नियमों की जानकारी नही है या फिर उन्हें इस बात का ज्ञान नही है कि यातायात नियमों का पालन नही करने से जुर्माना के अलावा भी भयावह परिणाम हो सकते है। यह तो मानना होगा कि यातायात पुलिस इन नियमों का पालन करने के प्रति लोगों को जागरुक करने अपनी ओर से जागरुक करने, समझाइश देने और सतर्क करने में कोई कसर नही छोड़ता फिर भी लोग अपनी हरकतों से बाज नही आते। वस्तुतः जो न समझे उसे समझाया जा सकता है लेकिन जो समझकर और जानकर भी नही समझना चाहे उसे कैसे समझाया जा सकका है। दरअसल आजकल लोगों में ऐसी प्रकृति घर करने लगे है कि वे नियमानुकूल या कहे नियमों को मानकर चलने की बजाय नियमों से बचकर या उसे धोखे में रखकर चलने की अधिक कोशिश करने लगे है मगर वे शायद इस सच्चाई से वाकिफ नही है कि ऐसा करके वे अगर कभी यातायात कर्मी के आंखों में धूल झोंक भी लें लेकिन कब स्वयं के साथ धोखा कर लेगे उसका उन्हें पता भी नही चलेगा और वो धोखा इतना भयावह हो सकता है कि सारा जीवन भी पछताने के लिए कम पड़ जाय।

यातायात नियमों की अवहेलना पर जुर्माना तो सबसे छोटी सजा समझी जानी चाहिए। आए दिन सड़कों पर इसी एक वजह से दिखाई देने वाले दिल दहला देने वाले दृश्य उसकी बड़ी सजा के रुप है। यह सब कुछ देख सुनकर भी लोग यातायात नियमों के प्रति इतने वेपरवाह कैसे हो सकते हैं यह समझ से बाहर है।

सुरक्षित और निर्वाध रुप से जीवन संचालित करने के लिए अनुशासन और नियमों का परिपालन आवश्यक है, इतनी समझ तो हर सामान्य व्यक्ति में होती है और होनी भी चाहिए। फिर भी अगर वह इनका परिपालन नही करता या इनसे इनकी अनदेखी करता है तो यही तात्पर्य है कि वह जानबूझकर ऐसा कर रहा है। अक्सर युवा वर्ग में ऐसी प्रवृत्ति देखी जाती है। उम्र के जोश में वे होश जरुर खो देते है मगर यह नही समझते कि अगर कोई हादसा हो गया तो परिजनों पर क्या बीतेगी। जुर्माना तो पिता के जेब से जाता है अतएव उसका कोई प्रभाव उन पर नही होता और कई कई बार एक ही गल्ती को दोहराते है। एक तरह से देखा जाए तो अधिकतर माता पिता अपने किशोर और युवा बच्चों के आगे विवश से होते है। चाह कर भी वे न उन्हें अनुशासन हीनता से रोक सकते है और न उनकी समझाइश की परवाह कोई करता है।

सर्वाधिक चिंता तो उन वाहन चालकों के संदर्भ में होती है जो यात्री वाहन चलाते है। इस बात को नजरंदाज कर कि उन पर कितने सारे लोगों की सुरक्षा निर्भर है वे यातायात नियमों के साथ मनमानी करने का दुस्साहस करते है। नतीजा कया हो सकता है यह सर्वज्ञात है।

अतः यही कहा जा सकता है कि घोड़े को नदी किनारे ले तो जाया जा सकता है पर वह कब तक पानी नही पिता जब तक उसे प्यास न लगे। उसी तरह चाहे कितना ही जागरुकता कार्यक्रम, समझाइश और जुर्माना क्यों न हो व्यक्ति तभी नियमों को अपनाएग जब वह स्वयं ऐसा करना चाहेगा।

राज-काज

कैमरा, कोण और दृष्टिकोण से समृद्ध राजनीति

राजनीति में तीन चीजें–कैमरा, कोण और दृष्टिकोण अत्यन्त महत्वपूर्ण है। जिस नेता ने इन चीजों को अच्छे से समझ लिया, सफलता उसके कदमों में होती है। बटुक जी ऐसे ही नेता हैं इसलिए सफलता के शिखर पर हैं। उनका दृष्टिकोण साफ है। पार्टी और नीतियां एक सीमा तक ही उन्हें बांधकर रख पाती हैं। अपने जमीर, अपनी अंतरात्मा को उन्होंने इस भार से मुक्त रखा है। निष्ठा और भावनात्मक लगाव जैसे शब्द उन्होंने राजनीति के शुरुआती दिनों में ही अपने शब्दकोश से बाहर कर दिए थे।

रोहनात गांव जहां आज़ादी के 71 साल बाद लहराया तिरंगा

दरअसल यह 1857 के गदर या सैनिक विद्रोह, जिसे स्वतंत्रता की पहली लड़ाई भी कहते हैं, के दौरान ब्रिटिश अधिकारियों के कत्लेआम की जवाबी कार्रवाई थी। रोहनात गांव हरियाणा के हिसार ज़िले के हांसी शहर से कुछ मील की दूरी पर दक्षिण.पश्चिम में स्थित है। गांव रोहनात आजादी के रणबांकुरों के नाम से जाना जाता है। यहां के लोगों ने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अंग्रेजों से लोहा लेते हुए देश की आजादी के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए थे।

गांव के वीर जांबाजों ने बहादुरशाह जफर के आदेश पर 29 मई 1857 के दिन अंग्रेजी हुकूमत की ईंट से ईंट बजा दी। इस दिन ग्रामीणों ने जेलें तोड़कर कैदियों को आजाद करवाया। 12 अंग्रेजी अफसरों को हिसार और 11 को हांसी में मार गिराया। इससे बौखलाकर अंग्रेजी सेना ने गांव पुठ्ठी के पास तोप लगाकर गांव के लोगों को बुरी तरह भून दिया। सैंकड़ों लोग जलकर मर गए, फिर भी ग्रामीण लड़ते रहे। अंग्रेजों के जुल्म के आगे यहां के ग्रामीण निडर होकर डटे रहे और उन्होंने अंग्रेजों के जुल्म को भी सहा। अंग्रेजों ने यहां के गांव को तोप से तबाह कर दिया।

अंग्रेजों ने इसके बाद भी जुल्मों को जारी रखा। औरतों और बच्चों को कुएं में फेंक दिया। दर्जनों लोगों को सरे आम जोहड़ के पास पेड़ों पर फांसी के फंदे पर लटका दिया। ये कुएं और पेड़ आज भी अंग्रेजी हुकूमत के जुल्मों के जीते जागते सुबूत हैं। इस गांव के लोगों पर अंग्रेजों के अत्याचार की सबसे बड़ी गवाह हांसी की एक सड़क है। इस सड़क पर बुल्डोजर चलाकर इस गांव के अनेक क्रांतिकारियों को कुचला गया था, जिससे यह रक्त रंजित हो गई थी और इसका नाम लाल सड़क रखा गया था। महिलाओं ने भी अंग्रेजों से आबरू बचाने के लिए गांव स्थित ऐतिहासिक कुएं में कूदकर जान दे दी थी।

> आजादी की लड़ाई में भारत के लाखों शूरवीरों ने अपने प्राण न्यौछावर किए थे। मगर आज कुछ यादों को संजोया गया है तो कुछ की किसी को जानकारी ही नहीं है। इसी में शामिल थी 1857 की क्रांति की एक कहानी, जिसमें अंग्रेजी सेना के छक्के छुड़ाने वाले गांव रोहनात हिसार (हरियाणा) के वीर थे। वो 29 मई 1857 की तारीख थी। हरियाणा के रोहनात गांव में ब्रिटिश फौज ने बदला लेने के इरादे से एक बर्बर खूनखराबे को अंजाम दिया था। बदले की आग में ईस्ट इंडिया कंपनी के घुड़सवार सैनिकों ने पूरे गांव को नष्ट कर दिया। लोग गांव छोड़कर भागने लगे और पीछे रह गई वो तपती धरती जिस पर दशकों तक कोई आबादी नहीं बसी।

डेढ़ सौ साल बीत जाने के बाद आज भी गांव उस सदमे से उबर नहीं सका। गांव के बुजुर्ग कुंए को देख कर उस डरावनी कहानी को याद करते हैं। गांव के घरों को तबाह करने के लिए आठ तोपों से गोलों बरसाए गए। जिसके डर से औरतें और बच्चे बुजुर्गों को छोड़ कर गांव से भाग गए। अंधाधुंध दागे गए गोलों की वजह से लगभग 100 लोग मारे गए, पकड़े गए कुछ लोगों को गांव की सरहद पर पुराने बरगद के पेड़ से लटका कर फ़ांसी दे दी गई। जिसने भी ब्रिटिश अधिकारियों को मारने की बात कबूल की, उन्हें तोप से बांध कर उड़ा दिया गया। इस घटना के महीनों बाद तक यहां कोई इंसान नज़र नहीं आया।

14 सितंबर 1857 को अंग्रेजों ने इस गांव को बागी घोषित कर दिया। 13 नवंबर को पूरे गांव की नीलामी के आदेश दे दिए गए। 20 जुलाई 1858 को गांव की जमीन व मकानों तक को नीलाम कर दिया गया। इस जमीन को पास के पांच गांवों के 61 लोगों ने महज 8 हजार रुपये की बोली में खरीदा था। अंग्रेज सरकार ने फिर फरमान भी जारी कर दिया कि भविष्य में इस जमीन को रोहनात के लोगों को न बेचा जाए। मगर समय बीतने के साथ धीरे.धीरे स्थिति सामान्य हो गई और यहां के लोगों ने अपने रिश्तेदारों के नाम कुछ एकड़ जमीन खरीदकर दोबारा गांव बसाया।

रोहनात गांव में 23 मार्च 2018 से पहले कभी भी आजादी का जश्न नहीं मनाया गया था और न ही गांव में राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया था, क्योंकि यहां के ग्रामीणों की मांग को पूरा करने के लिए किसी भी सरकार ने ध्यान नहीं दिया। इसी रोष स्वरूप यहां के लोगों ने आजादी का जश्न नहीं मनाया था। लोगों को यह मलाल रहा कि देश की आजादी के लिए अपना सब कुछ खो देने के बावजूद उन्हें वह जमीन तक नहीं मिली, जिसके लिए वे लड़ाई लड़ते रहे। इसी बात से खफा होकर ग्रामीणों ने यहां कभी झंडा नहीं फहराया था।

कुछ समय पहले तक भी कुछ जमीन पर विवाद रहा। वर्तमान सरकार ने इस विवाद को निपटवाया। इसके बाद 23 मार्च 2018 को पहली बार मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने गांव के बुजुर्ग के हाथों राष्ट्रीय ध्वज फहराकर यहां के लोगों को गुलामी के अहसास से आजाद करवाया। देश की आजादी में म्हारे गांव रोहनात के बुजुर्गों के योगदान को अब सभी जान पाए इसलिए रोहनात गांव के बुजुर्गों के योगदान पर दास्तान ए रोहनात नाटक बना है। नाटक में 1857 की क्रांति में गांव रोहनात के बलिदान को दिखाया गया है जिसे देखने के लिए देश भर के लोगों में विशेष उत्साह है।

.सत्यवान सौरभ
(ये लेखक के अपने विचार है)

रक्त.रंजिश परंपरा से कब मुक्त होगा पश्चिम बंगाल

पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के बगटूई गांव में शोक और सन्नाटे का आलम चारों ओर पसरा है। आग से जली लाशें इस प्रकार फैली पड़ी है मानो किसी फिल्म में किसी अनचाही दुर्घटना का सीन देख रहे हों।

तृणमूल कांग्रेस के एक नेता की हत्या के बाद पश्चिम बंगाल के इस क्षेत्र में जो गुंडागर्दी की गईए उसी के परिणामस्वरूप आगजनी की घटना में गांव के दो बच्चों और तीन महिलाओं सहित आठ लोगों की मौत हो गई जिसके बाद से गांव में सियासी हलचल तेज हो गई है। बुधवार को सीपीएम और बीजेपी के प्रतिनिधि बोगटुई गांव पहुंचे थेए अतः निंदा तो निश्चित रूप से होनी ही थी। विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने मामले की जांच सीबीआई और एनआईए से कराने की मांग की है। फिलहाल गांव में डर का माहौल है। बड़ी तादाद में पुलिस और रैपिड ऐक्शन फ़ोर्स के जवानों को तैनात किया गया है। खूनी जल्लाद अपनी आकाओं की शरण में सुरक्षित दुबके हुए हैं।

8 लोगों की हत्या के इस मामले के बाद एक बार फिर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्यपाल जगदीप धनखड़ आमने.सामने आ गए हैं। धनखड़ इसे लोकतंत्र और इंसानियत के लिए शर्मसार कर देने वाली घटना बता रहे हैं। राज्यपाल के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से एक वीडियो पोस्ट किया गया है जिसमें वो राज्य की ममता बनर्जी सरकार पर भड़कते भी नज़र आ रहे हैं। वहीं ममता बनर्जी ने राज्यपाल धनखड़ को मामले पर श्अनुचित बयानश् देने से परहेज़ करने के लिए कहा है। यानि तुम जुल्म करते जाओ और हम चूँ भी न करें। घटना का दुखद पहलु यह भी है कि पश्चिम बंगाल में बीरभूम में हिंसा के मामले में फॉरेंसिक रिपोर्ट में चौंकाने वाला दावा किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिकए मृतकों को जिंदा जलाने से पहले बुरी तरह से पीटा गया था अर्थात् मृतकों को पीट.पीटकर अधमरा कर दिया गया तत्पश्चात सबूत नष्ट करने के लिए एवं अन्य लोगों में दहशत का माहौल बनाने के लिए उन वहशी.दरिंदो ने उन असहायों को मकान में बंद कर जिंदा जला डाला।

राज्यपाल धनखड़ ने इस घटना को ष्भयानक हिंसा और आग़जनी का तांडवष् बताया और कहा कि उन्होंने राज्य के मुख्य सचिव से इस घटना पर तत्काल अपडेट मांगा है।

राज्यपाल धनखड़ ने कहा कि राज्य को हिंसा और अराजकता की संस्कृति का पर्याय नहीं बनने दिया जा सकता। अपने बयान में राज्यपाल ने राज्य सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि प्रशासन को ष्पक्षपातपूर्ण हितों से ऊपर उठने की ज़रूरत है और यह होता नहीं दिख रहा है।ष् इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस मामले में कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल हॉल में वर्चुअल माध्यम से एक गैलरी का उद्घाटन करते वक्त बीरभूम में मारे गए लोगों के प्रति संवेदना प्रकट करते हुए कहाए ष्सबसे पहले मैं पश्चिम बंगाल के बीरभूम में हुई हिंसक वारदात पर दुख व्यक्त करता हूँ ए अपनी संवेदना व्यक्त करता हूँ। मैं आशा करता हूं कि राज्य सरकार बंगाल की महान धरती पर ऐसा जघन्य पाप करने वालों को अवश्य ही सजा दिलाएगी।श्

प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल को महान धरती कह कर संबोधित किया है क्योंकि पश्चिम बंगाल को पश्चिम देशों के लोग भारत का व्यापार द्वार मानते थे। अंग्रेजी हुकुमत भी इसी दिशा से व्यापारी के भेष में भारत में घुसी थी और अंग्रेजी हुकुमत को भगाने के लिए क्रांति की ज्वाला भी यहीं से उठी थी।

विवेकानंदए रवींद्रनाथ टैगोरए क्रांतिकारी शचीन्द्रनाथ सान्यालए रासबिहारी बोसए नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे क्रांतिकारियों में से एक महर्षि अरविंद घोष देश की आध्यात्मिक क्रांति की पहली चिंगारी थे। उन्हीं के आह्वान पर हजारों बंगाली युवकों ने देश की स्वतंत्रता के लिए हंसते.हंसते फांसी के फंदों को चूम लिया था। अंग्रेजों के विरुद्ध सन् 1763 से 1773 तक चला संन्यासी आंदोलन सबसे प्रबल आंदोलन था। आदिगुरु शंकराचार्य के दसनामी संप्रदाय ने एकजुट होकर भारतीय धर्म और संस्कृति को बचाने के लिए शस्त्र युद्ध का बिगुल बजाया। इतिहास प्रसिद्ध इस विद्रोह की स्पष्ट जानकारी बंकिमचन्द्र चटर्जी के उपन्यास श्आनंद मठश् में मिलती है। इस विद्रोह को कुचलने के लिए श्वारेन हेस्टिंग्सश् को कठोर कार्रवाई करनी पड़ी थी। उसने बेरहमी से संन्यासियों और हिन्दू जनता का कत्लेआम किया। इस आंदोलन के बाद देश का संन्यासी जाग्रत हो गया। सशस्त्र क्रांति के पीछे उनकी ही प्रेरणा थी। अरविंद ने कहा था कि चाहे सरकार क्रांतिकारियों को जेल में बंद करेए फांसी दे या यातनाएं देए पर हम यह सब सहन करेंगे और यह स्वतंत्रता का आंदोलन कभी रुकेगा नहीं। इसीप्रकार शचीन्द्रनाथ सान्याल की ष्इंडियन रिपब्लिकन आर्मीष् वर्कशॉप से रामप्रसाद बिस्मिलए पंडित चन्द्रशेखर आजाद व भगतसिंह जैसे क्रांतिकारी निकले थे।

पश्चिम बंगाल में राजनीतिक विरोध के कारण होने वाली सामूहिक हत्याएं कोई नई नहीं हैं। इनकी शुरुआत तो सत्तर के दशक में ही हो गई थीं। उसके बाद बंगाल इस मामले में कई बार सुर्खियों में रहा है। 2011 को पश्चिम मेदिनीपुर के नेताई में ऐसी खूनी झड़प में 14 लोग मारे गए थे। मुर्शिदाबाद ज़िले में भी खासकर पंचायत चुनावों के दौरान सीपीएम और कांग्रेस के बीच हिंसा में काफ़ी लोग मरते रहे हैं। 2007 में पूर्व मेदिनीपुर ज़िले के नंदीग्राम में पुलिस फायरिंग में 14 लोगों की मौत ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियां बटोरी थी। लेकिन उससे कोई सात साल पहले 27 जुलाईए 2000 में इसी बीरभूम ज़िले के नानूर में सीपीएम और तृणमूल कांग्रेस के आपसी संघर्ष में 11 लोगों की मौत हो गई थी। तब एक विवादास्पद जमीन पर खेती के लिए जाने वाले 11 मज़दूरों पर कथित सीपीएम समर्थकों ने हमला किया था। मरने वाले सभी लोग टीएमसी समर्थक थे। अब बीरभूम के बोगटुई में आठ लोगों को जला कर मारने की घटना भी इसी सिलसिले की कड़ी है।

राजनीति शास्त्र के प्रोफ़ेसर रहे सुकुमार घोष कहते हैंए ष्भद्रलोक वाले बंगाल में हिंसा और खूनी संघर्ष की परंपरा तो साठ के दशक के आखिर में नक्सल आंदोलन के दौरान ही शुरू हो गई थी। लेकिन राजनीतिक वर्चस्व के कारण होने वाली हिंसक झड़पें नब्बे के दशक में शुरू हुई तब कांग्रेस मजबूत थी तो सीपीएम और उसके बीच हिंसा होती थी। बाद में टीएमसी ने कांग्रेस की जगह ले ली। लेकिन टीएमसी के सत्ता में आने के बाद पहली बार इस घटना के ज़रिए अंदरखाने की लड़ाई खुल कर सामने आई है। पश्चिम बंगाल हाल के वर्षों में अक्सर राजनीतिक हिंसा और हत्याओं के लिए सुर्खियों में रहा है। लेकिन यह पहला मौका है जब एक साथ इतने लोगों के मारे जाने के बावजूद पुलिसए प्रशासनए टीएमसी समेत कोई भी पार्टी इसे राजनीतिक हत्या नहीं बता रही है।

ममता बनर्जी ने सभी मृतकों के परिजनों को 5.5 लाख रुपएए जिन घरों को नुकसान पहुंचा हैए उनके निर्माण के लिए 2.2 लाख रुपए और घायलों को 50.50 हजार रुपए की आर्थिक मदद देने का ऐलान कर मरहम लगाने का तो प्रयास किया है किंतु अपने खूनी कार्यकर्ताओं की मानसिकता पर अंकुश कब लगायेगीए इसके लिए देश प्रतीक्षा कर रहा है।

. डॉ उमेश प्रताप वत्स
(ये लेखक के अपने विचार है)

कठिन डगर है विपक्षी एकता की

> वर्ष 2024 में होने वाले लोकसभा चुनावों और इस वर्ष राष्ट्रपति चुनाव के मद्येनज़र देश में एक बार फिर विपक्ष की एकता के लिए जोरदार प्रयास किये जा रहे है। बीरबल की खिचड़ी की तरह विपक्ष की एकता के प्रयास परवान चढ़ेंगे या बीच मंझधार में रह जायेंगे कोई बताने वाला नहीं है।

यह सिर्फ शिगूफा है या चूं चूं का मुरब्बा यह देखने वाली बात है। इस बार विपक्ष की यह एकता कथित साम्प्रदायिकता के खिलाफ है या भाजपा को सत्ताच्युत करने का प्रयास देखने वाली बात है। विपक्ष की यह एकता सिद्धांतों पर आधारित है या अवसरवादी और सुविधा की राजनीति इस पर भी गौर करने की बात है।

वर्तमान में विपक्ष कांग्रेस नीत यूपीए के साथ गैरकांग्रेस और गैरभाजपा की सियासत करने वाले दलों में विभाजित है। पांच राज्यों में विधानसभा चुनावों में बुरी तरह पराजित होने के बाद कांग्रेस की सांस उखड़ी हुई है। विपक्ष पहले से ही कई धड़ों में विभाजित है। चार राज्यों में भाजपा की जीत के बाद इनके मुंह लटक गए है। गैरभाजपा और गैरकांग्रेस का नारा बुलंद करने वाले तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव और बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लाख प्रयासों के बाद भी अब तक कोई सशक्त मोर्चा बन नहीं पाया है। ममता बनर्जी और चंद्रशेखर राव 2024 में नरेंद्र मोदी सरकार को सत्ता बेदखल करने के लिए विपक्षी एकता की कवायद में जुटे हैं। इस मोर्चे के नहीं बन पाने के मुख्य कारणों में शरद पवारए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे है। इन तीनों नेताओं के कांग्रेस के साथ साझेदारी के सम्बन्ध प्रस्तावित मोर्चे के गठन में रोड़े अटकाए हुए है। चुनावों में हार के बाद एक बार फिर विपक्षी एकता में फूट पड़ती दिख रही है। ममता बनर्जी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए एंटी बीजेपी और एंटीकांग्रेस अलायंस बनाने का आह्वान किया है। सपा सुप्रीमों अखिलेश यादव के सम्बन्ध भी कांग्रेस से अच्छे नहीं है। राजद के तेजस्वी यादव भाजपा के खिलाफ बनने वाले किसी भी मोर्चे का आंख मूंद कर साथ देने को तैयार है। उड़ीसा के सी एम पटनायक और आंध्र के सीएम फ़िलहाल किसी मोर्चे के साथ नहीं है। हालाँकि इन दोनों की भाजपा के साथ नरमी किसी से छिपी नहीं है। दिल्ली के बाद पंजाब में सरकार बनाने वाली आम आदमी पार्टी भाजपा के सख्त खिलाफ है मगर कांग्रेस का साथ देने को तैयार नहीं है। वाम मोर्चे की हालत सांप छुछुंदर जैसी है। अन्य क्षेत्रीय दल भी आपस में बंटे हुए है। विपक्ष की ऐसी स्थिति भाजपा के लिए सुखद कही जा सकती है।

छिन्न भिन्न हो रही विपक्षी एकता की कवायद के बीच चूँकि चार महीनें बाद राष्ट्रपति का चुनाव होने जा रहा है। वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 25 जुलाई 2022 को समाप्त होने जा रहा है। राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया जून से शुरू होने के आसार हैं और जुलाई में चुनाव होंगे। चार राज्यों में भाजपा की जीत से शरद पवारए ममता और केसीआर जैसे नेताओं के मंसूबों पर पानी फिर गया है। इन नेताओं को राष्ट्रपति निर्वाचन के लिए अब नए सिरे से अपनी रणनीति बनानी होंगी। चार राज्यों के नतीजे भाजपा के अनुकूल आने से विपक्ष का चक्रव्यूह ताश के पतों की तरह धराशाही हो गया। भाजपा के चार राज्यों में जीत के बाद हौसले बुलंद है। यह भी कहा जा रहा था कुछ नेता समूचे विपक्ष को एकजुट करने में लगे है ताकि राष्ट्रपति निर्वाचन में भाजपा को झुकाया और छकाया जा सके। भाजपा को एनडीए के साथी दलों के अलावा आंध्रप्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी की वाई एस आर कांग्रेस पार्टी और ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक की बीजू जनतादल जैसी पार्टियों की मदद मिलने का पूरा भरोसा है। पांच राज्यों में हुए विधान सभा चुनावों में से चार में भाजपा की जीतने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस साल होने वाले राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए एक मजबूत स्थिति में ला दिया है। दूसरी तरफ विभाजित विपक्ष की एकता के नारे एक बार फिर बुलंद होने लगे है। राष्ट्रपति चुनाव के दौरान विपक्ष की एकता पर सब की निगाह लगी है। यह एकता सिर्फ राष्ट्रपति चुनाव तक दिखावे की रहेगी अथवा दमदार है यह देखने वाली बात है। विपक्षी एकता के प्रयास का असली मकसद 2024 में भाजपा को हराना है। बहरहाल विपक्ष की एकता के नगाड़े कुछ नेताओं ने बजाने शुरू कर दिए है।

बालमुकुन्द ओझा
(ये लेखक के अपने विचार है)